<u>पंचायती राज मंत्रालय</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की नवंबर, 2018 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1. नवंबर महीने के दौरान "सबकी योजना सबका विकास" के तहत व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान में काफी प्रगति हुई है। इस महीने के दौरान, 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों (लगभग 20%) में सुविधा प्रदाता नियुक्त थे, जो राष्ट्रीय गणना के आंकड़ों को 2.2 लाख (लगभग 90%) तक ले कर गए और 16,000 ग्राम पंचायतों ने मिशन अंत्योदय के डेटा अपलोड किए, जिससे संचयी आंकड़ा 2.1 लाख ग्राम पंचायतों तक पंहुच गया। इसके अलावा , विशेष ग्राम सभा के कार्यक्रम निर्धारण और संचालन में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिसमें इस महीने के दौरान लगभग 25% की वृद्धि देखी गई। वीडियो सम्मेलन, हितधारकों की बैठकें और राज्यों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरे भी किए गए ।इस अभियान के जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बदलने में एक लंबा सफर तय करने की संभावना है ।

2. जनजातीय लोगों की विशिष्ट जरूरतों को समझते हुए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी और पीआर), हैदराबाद में दिनांक 2-3 नवम्बर,2018 को "पेसा राज्यों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विस्तृत विचार-विमर्श में 10 पेसा राज्यों के प्रतिनिधियों; कुडुम्बश्री, तिरुवनंतपुरम सहित सात मंत्रालयों/संस्थानों; एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय); केंद्रीय सिल्क बोर्ड इत्यादि द्वारा भाग लिया गया। जीपीडीपी के लिए अभिसरण और क्षमता निर्माण; न्यायसंगत विकास के लिए पीआरआई-एसएचजी अभिसरण; पीईएसए क्षेत्रों में व्यापक जीपीडीपी के लिए जल संसाधन और कृषि विकास और लघु वनोपज के प्रबंधन के लिए योजना पर महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई।

3. एक और दो दिवसीय कार्यशाला "हिमालयन राज्यों में जीपीडीपी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन" विषय पर 11 -12 नवंबर, 2018 को शिमला में आयोजित की गई।पांच हिमालयन राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के 113 प्रतिनिधियों और 11 मंत्रालयों/संस्थानों के संसाधन व्यक्तियों सहित;

डिफेंस इनस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, लेह; कुडुम्बश्री; एनआरएलएम, ग्रामीण विकास मंत्रालय; सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्पेरेट हॉर्टिकल्चर, कश्मीर; जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोईल एंड वॉटर कंजर्वेशन, देहरादून इत्यादि ने कार्यशाला के गहन और व्यापक विचार-विमर्श में भाग लिया। कार्यशाला के दौरान श्री वीरेंद्र कंवर, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश ने "ग्रामसभा पर दिशानिर्देश" जारी किए।

4. इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, "पूर्वोत्तर राज्यों में जीपीडीपी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन" विषय पर 16 -17 नवंबर 2018 के दौरान एनआईआरडी और पीआर, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटीमें एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 79 प्रतिभागियों और कृषि मंत्रालय, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय कुडुम्बश्री; एनआरएलएम, एमओआरडी; जैविक कृषि, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय सक्षमता केंद्र; भारतीय प्लाईवुड औद्योगिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं आदि सहित 11 मंत्रालयों/संस्थानों; ने कार्यशाला के विचार-विमर्श में भाग लिया। सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने व्यापक जीपीडीपी के लिए रोडमैप विकसित किए।

5. इस वर्ष आरजीएसए की पुनर्गठित योजना की शुरूआत के बाद, आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक 12 अक्तूबर, 2018 को आयोजित की गई। सीईसी द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और एनआईआरडी और पीआर को 23.75 करोड़ रूपये निधियों के रूप में जारी किए गए थे।

6. नवंबर 2018 के दौरान, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुशंसा की है कि चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के तहत वर्ष 2018-19 के लिए मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को 180.815 करोड़ रुपये रुपये, गुजरात को 862.68 करोड़ रुपये और सिक्किम को 14.835 करोड़ रुपये जारी किए जाएं।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने हेतु राज्यों को सख्त निदेश दे रहा है। इस संबंध में,

मंत्रालय वीडियो सम्मेलन आयोजित कर रहा है; वर्ष 2017-18 के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाते को बंद करने, ग्राम पंचायत/विक्रेता पंजीकरण के लिए राज्यों पर जोर दे रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए, 89% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता बंद कर दिया है और 1,33,532 ग्राम पंचायतें पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं जबकि शेष ग्राम पंचायतों में ये प्रक्रियाधीन है।

8. इसके अलावा, सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों में एलजीडी कोड को अपनाने पर बड़ा जोर दिया गया है; एलजीडी कोड के साथ ग्राम पंचायत को मैप करने के लिए मंत्रालय पीएफएमएस टीम के साथ इस मामले का संज्ञान ले रहा है। अब तक, 90% ग्राम पंचायतों को एलजीडी कोड के साथ मैप किया गया है।

9. एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़ में पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) अनुप्रयोगों पर 28-30 नवंबर, 2018 को मुख्य रूप से ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, जियो-टैगिंग और लोकल सरकारी डायरेक्टरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

10. पंचायत योजना के प्रोत्साहन के तहत पंचायत पुरस्कार-2019 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), नानाजीदेमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार की श्रेणियों के तहत ऑनलाइन नामांकन राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य (यूटी) प्रशासनों से आमंत्रित किए गए हैं। दिनांक 14.11.2018 को विभिन्न संबंधित मुद्दों के साथ-साथ पंचायत पुरस्कार-2019 के लिए ऑनलाइन नामांकन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया।

****

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of November, 2018

1. The people’s plan campaign for preparing comprehensive Gram Panchayat Development Plan under “Sabki Yojana Sabka Vikas” made substantial progress during the month of November. During this month, more than 50,000 GPs (approx. 20%) had facilitators assigned to them, taking the national count to 2.2 lakh. (approx. 90%) and 16,000 GPs uploaded the Mission Antodaya data, taking the cumulative figure to 2.1 lakh GPs. Moreover, the most significant progress was observed in the scheduling and conducting of special Gram Sabhas, which saw a nearly 25% increase during the

month. Video Conferences, stakeholder meetings and visits of senior ministry officials to States were also undertaken. The campaign is likely to go a long way in transforming governance and service delivery at the grass root level.

2. In due appreciation of specific needs of tribal people, MoPR organised a Workshop on "Economic and Social Transformation through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) in PESA States" at National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad during 2nd-3rd November, 2018. The detailed deliberations in the workshop were participated by representatives of 10 PESA States; seven Ministries/Institutions including Kudumbashree, Thiruvananthapuram; NRLM, Ministry of Rural Development (MoRD); Central Silk Board etc. Important recommendations emerged on Convergence and Capacity Building for GPDP; PRI-SHG Convergence for Equitable Development; Planning for Water Resources and Agricultural Development and Management of Minor Forest Produce for comprehensive GPDP in PESA areas.

3. Another two day's workshop on "Economic and Social Transformation through GPDP in Himalayan States" was organized at Shimla during 11th-12th November, 2018. 113 delegates from 5 Himalayan States viz. Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttrakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim and resource persons from 11 Ministries/Institutions including; Defence Institute of High Altitude Research, Leh; Kudumbashree; NRLM, MoRD; Central Institute of Temperate Horticulture, Kashmir; GB Pant Institute of Himalayan Environment and Sustainable Development, Almora, Uttarakhand; Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun etc. participated in intensive and extensive deliberations of the workshop. During the workshop Shri Virender Kanwar, Hon'ble Rural Development & Panchayati Raj Minister, Himachal Pradesh released the "Guidelines on Gram Sabha".

4. Moreover, MoPR also organised a workshop on "Economic & Social Transformation through GPDP in North Eastern States" during 16th-17th November, 2018 at NIRD&PR, North-East Regional Centre, Guwahati. 79 Participants from 8 North Eastern States and 11 Ministries/Institutions including Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare; Kudumbashree; NRLM, MoRD; International Competence Centre for Organic Agriculture, National Fisheries Development Board; Indian Plywood Industries Research & Training Institute, Ministry of Environment, Forests & Climate Change; UN Women etc. participated in deliberation of the workshop. All North Eastern States developed road map for comprehensive GPDP.

5. After the launching of the restructured scheme of RGSA this year, the first meeting of the Central Empowered Committee (CEC) of RGSA was held on 12th October, 2018. The funds to the tune of Rs. 23.75 crore were released to the States of Maharashtra, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland and NIRD & PR as per the decisions taken by the CEC.

6. During November 2018, the Ministry has recommended to Ministry of Finance the release of 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 180.815 crore to Himachal Pradesh, Rs. 862.68 crore to Gujarat and Rs. 14.835 crore to Sikkim for 2018-19 under Fourteenth Finance Commission(FFC).

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 89% of the Gram Panchayats have closed their account books and 1,33,532 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same.

8. Further, with a major emphasis on adopting LGD codes across all the Central Government Ministries and State Governments; the Ministry is thoroughly pursuing with the PFMS team to get the GPs mapped with LGD codes. As on date, 90% of Gram Panchayats are mapped with LGD codes.

9. A three day residential workshop cum training was held at MGSIPA, Chandigarh on Panchayat Enterprise Suite (PES) Applications from November 28 – 30, 2018 focusing mainly on e-Financial Management System, Public Financial Management System, Geo-tagging and Local Government Directory.

10. For Panchayat Awards-2019 under the Incentivization of Panchayats scheme, online nominations under the categories of Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP), Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP) and Gram Panchayat Development Plan (GPDP) Award have been invited from State Governments/Union Territory (UT) Administrations. A Video Conference was held on 14.11.2018 with the States/UTs to discuss the status of online nominations for Panchayat Awards-2019 alongiwth various related issues.

****